Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

वर्ष- 29 ◻ अंक- 35 ◻ रायपुर, गुरुवार 26 फरवरी 2026 ◻ पृष्ठ-8 ◻ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

धान खरीदी पर विपक्ष ने रखा स्थगन प्रस्ताव, अग्राह्य होते ही नारेबाजी करते गर्भगृह में पहुंचे कांग्रेस विधायक, निलंबित

रायपुर, 26 फरवरी (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन शून्यकाल में विपक्ष ने धान खरीदी का मुद्दा उठा. नेता प्रतिपक्ष ने सरकार की नीति को फेल बताते हुए विस्तार से चर्चा के लिए स्थगन का प्रस्ताव दिया. सभापति के स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य करने पर कांग्रेस विधायक सदन में नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में पहुंचे. इसके साथ ही सदस्य सदन से स्वमेव निलंबित हुए.

नेता-प्रतिपक्ष **डॉ. चरण दास महंत** ने कहा कि धान खरीदी के मामले में सरकार की नीति फेल रही है. किसान परेशान होते रहे. पहले दिन से ही किसानों को चोर समझा. किसानों का पूरा धान नहीं खरीदा गया. किसानों को टोकन के नाम पर परेशान किया गया. अंग्रेजों के जमाने से भी बुरी स्थिति रही है. इस पर हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है. इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए. उमेश पटेल ने कहा कि किसानों का कर्ज काफी की जाए. और नहीं तो फिर से किसानों से खरीदी की जाए. **संगीता सिन्हा** ने कहा कि किसानों को धान का समपर्ण कराने मजबूर किया गया है. बालोद जिले में किसानों का पूरा धान नहीं खरीदा गया. **राघवेंद्र सिंह** ने कहा कि किसानों को जांजगीर जिले में खरीदी के लिए बहुत परेशान होना. किसान को प्रताड़ित होकर जहर पीना. एक किसान को टॉवर पर चढ़ना पड़ गया. व्यास कश्यप ने कहा कि जांजगीर जिले में 93 प्रतिशत किसान का ही धान खरीदा गया. किसानों को प्रताड़ित किया गया. किसानों को अपने हक के लिए लड़ना पड़ा है. उनके लिए एफआईआर हुई. **द्वारिकाधीश यादव** ने कहा कि धान और किसान का मुद्दा छत्तीसगढ़ के हित से जुड़ा है. किसान आज भी उम्मीद में है कि फिर से खरीदी होगी. लेकिन किसानों को परेशान करने काम किया गया. रामकुमार यादव ने कहा कि किसान को समर्पण कराने के लिए मजबूर किया गया. किसानों को डराने के लिए पुलिस को भेजा गया. **बालेश्वर साहू** ने कहा कि जो किसान धान नहीं बेच पाए हैं उनकी खरीदी होनी चाहिए. किसानों का कर्ज माफी होनी चाहिए. विक्रम मंडावी ने कहा कि किसानों का यह प्रदेश है. बस्तर से लेकर सरगुजा तक किसान परेशान हैं. किसानों के हित में स्थगन पर चर्चा होनी चाहिए. **भोलाराम साहू** ने कहा कि धान खरीदी के नाम पर किसानों को प्रताड़ित किया गया. किसानों को डराने और धमकाने का काम किया गया. किसानों की स्थिति बहुत खराब है. लोन लेकर खेती करने वाले किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो गए. **अंबिका मरकाम** ने कहा कि सिहावा क्षेत्र के किसान परेशान हुए. किसान इस बात दु:खी रहे कि उनका धान नहीं खरीदा गया. **कुंवर सिंह निषाद** ने कहा कि पूर्व विधायक को धान बेचने के लिए धरना देना पड़ा है. जनप्रतिनिधियों को, किसानों को परेशान होना पड़ा है. यशोदा वर्मा ने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र खैरागढ़ में किसानों को परेशान होना पड़ा है. किसानों का पूरा धान नहीं खरीदा गया. एक किसान ने परेशान होकर कलेक्ट्रेट के सामने आत्महत्या की कोशिश की. **ओंकार साहू** ने कहा कि धमतरी जिले में भी किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा है. रकबा समर्पण से किसानों की हालत खराब हुई है. किसान कर्ज में डूबे हुए हैं. **हर्षिता स्वामी बघेल** ने कहा कि डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बहुत से किसान धान नहीं बेच पाए हैं. वंचित किसानों की सुध ली जानी चाहिए. **अटल श्रीवास्तव** ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आज किसानों को हतोत्साहित करने का काम किया गया. किसान आज कर्जा में है. किसान को धान बेचने के लिए कई तरह से परेशान होना पड़ा है. सरकार किसानों के साथ नहीं है. **भूपेश बघेल** ने कहा कि सरकार की मंशा पहले स्पष्ट है कि धान और किसान पर चर्चा नहीं करानी है. छत्तीसगढ़ में आज अधिकारी राज चल रहा है. किसानों के घर में, खलिहान में जबरदस्ती प्रवेश किया गया. धान बेचने के लिए टोकन मांगने पर किसानों के घर अधिकारी भेजे गए, किसानों को चोर समझा गया. यह बेहद गम्भीर मामला है. इस पर चर्चा होनी चाहिए. भूपेश बघेल ने कहा कि मेरे घर पर भी अधिकारी बलात तरीके से घुसे थे. इस मामले में अगर चर्चा नहीं होती तो कम से कम सरकार की ओर से जवाब दिया जाना चाहिए. सभापति ने विपक्ष के स्थगन को अग्राह्य किया. सभापति ने कहा कि बजट सत्र में आय-व्यय पर चर्चा होती है. स्थगन अग्राह्य होने पर विपक्ष ने सदन में की नारेबाजी. गर्भगृह में पहुँचे सदस्य सदन से स्वमेव निलंबित हुए.

जेलों में एक साल में 66 बंदियों की मौत, 48 मामलों में जांच लंबित

गृहमंत्री ने सदन में दी जानकारी, आदिवासी नेता की मौत पर विपक्ष का हंगामा, वाकआउट

छत्तीसगढ़ की केंद्रीय एवं जिला जेलों में जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 तक कुल 66 बंदियों की कस्टोडियल डेथ हुई है। यह जानकारी विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान उप मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि 66 मामलों में से 18 प्रकरणों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच पूरी हो चुकी है, जबकि 48 मामलों में जांच की प्रक्रिया अभी जारी है। सदन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक आदिवासी नेता की मौत को हत्या करार देते हुए मामले की जांच विधानसभा की समिति से कराने की मांग की। इस मुद्दे पर सदन में जमकर नारेबाजी हुई। विपक्षी सदस्यों ने सदन की कार्यवाही से वाकआउट कर दिया।

इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आपत्ति जताते हुए कहा कि मृतकों के नाम और संबंधित जेलों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। उन्होंने पूछा कि क्या कवर्धा जेल में बंद पंकज साहू की कस्टोडियल डेथ इस सूची में शामिल है? साथ ही जीवन ठाकुर का मामला उठाते हुए कहा कि वे कांकेर जेल में बंद थे, लेकिन उनकी मृत्यु रायपुर में हुई। क्या यह प्रकरण भी 66 मामलों में शामिल है? इस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट किया कि पंकज साहू की मृत्यु मांगी गई अवधि से पहले की है, इसलिए वह इस आंकड़े में शामिल नहीं है। वहीं जीवन ठाकुर को कांकेर से न्यायालय की अनुमति के बाद रायपुर लाया गया था। भूपेश बघेल ने कहा कि जीवन ठाकुर आदिवासी समाज के प्रमुख नेता थे और गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे, लेकिन जेल में उन्हें समुचित उपचार नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी के विरोध में आदिवासी समाज ने प्रदर्शन भी किया था। गृहमंत्री ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जीवन ठाकुर के खिलाफ फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के प्रमाण मिलने पर कार्रवाई की गई थी। 12 अक्टूबर 2025 को उन्हें जेल लाया गया था। उन्हें शुगर की बीमारी थी और तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल भेजा गया था, जहां परिजन उनसे मिलते रहे। उन्होंने यह भी बताया कि जेल अधीक्षक ने न्यायालय को सूचित किया था कि वे उपचार में सहयोग नहीं कर रहे थे। जेल अस्पताल की रिपोर्ट के अनुसार, शुगर के मरीज होने के बावजूद वे आवश्यक परहेज नहीं करते थे। इसके बाद न्यायालय के निर्देश पर उनका स्थानांतरण रायपुर किया गया।इस पर भूपेश बघेल ने सवाल उठाया कि कोई भी शुगर का मरीज जानबूझकर अपनी हालत क्यों बिगाड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि उस समय उनका बेटा भी उसी जेल में था, लेकिन दोनों को अलग रखा गया। उनका तर्क था कि बेटा बेहतर देखभाल कर सकता था। साथ ही कांग्रेस विधायकों को भी मिलने की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया। भूपेश बघेल ने मामले की जांच विधानसभा की समिति से कराने की मांग की। इस पर गृहमंत्री ने कहा कि जब किसी मामले में पहले से मजिस्ट्रेट जांच चल रही हो, तो समानांतर जांच का औचित्य नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि हर व्यक्ति किसी न किसी समाज से जुड़ा होता है, इससे कानून की प्रक्रिया प्रभावित नहीं हो सकती। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी पूछा कि क्या नव्या मलिक का नाम इस सूची में शामिल है, जो कथित रूप से ड्रग रैकेट से जुड़ी थी। इस पर गृहमंत्री ने कहा कि वह इस संबंध में अलग से जानकारी प्राप्त कर अवगत कराएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में हत्या, लूट और फिरौती जैसे जघन्य अपराधों में 35 प्रतिशत वृद्धि के संबंध में सवाल उठाया। गृहमंत्री विजय शर्मा ने जवाब दिया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में अपराधों में कमी आई है।

ड्रग पैडलर नव्या मलिक का नाम सदन में गूंजा, भूपेश बघेल ने पूछा- आरोपियों की सूची से नाम गायब क्यों?

छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रदेश में ड्रग तस्करी का मुद्दा उठा. बहुचर्चित ड्रग पैडलर नव्या मलिक का नाम सदन में गूंजा. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गंभीर आरोप लगाए. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाया कि बहुचर्चित ड्रग पैडलर नव्या मलिक का नाम आरोपियों की सूची से गायब है. प्रश्न के उत्तर में दी गई जानकारी में नव्या मलिक का नाम क्यों नहीं है? आखिर नव्या का नाम क्यों छुपाया गया? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इस लापरवाही पर कोई कार्रवाई होगी? इस पर मंत्री ने कहा मुझे इसकी जानकारी नहीं है, परीक्षण करा लेंगे।

सदन में उठा नक्सलियों के सरेंडर और नक्सल पुनर्वास का मुद्दा

गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया 1496 ईनामी सहित 2937 नक्सलियों ने किया है आत्मसमर्पण

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन नक्सलियों के सरेंडर और नक्सल पुनर्वास का मुद्दा उठा. कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी के सवालों का गृह मंत्री विजय शर्मा ने आंकड़ों के साथ जवाब दिया. कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने सवाल किया कि नक्सल पुनर्वास नीति क्या है? 2023 से अब तक अब तक कितने नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया? इनामी नक्सलियों में से किन-किन को राशि दी गई कितनी देना बाकी है? इस पर जवाब देते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने सदन में बताया कि 9 फरवरी 2026 तक 1496 इनामी नक्सलियों को मिलाकर कुल 2937 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. उन्होंने बताया कि पुनर्वास नीति के तहत अब तक प्रारंभिक राशि के तौर पर नक्सलियों को 5 करोड़ 64 लाख रुपए दी गई है. ईनाम की 49 करोड़ 34 लाख रुपए की राशि दिया जाना शेष है. सरेंडर करने वाले नक्सलियों को राशि दे रहे हैं, जिसे 3 साल बाद वे बैंक से पैसे निकाल सकेंगे.

मुठभेड़ में 2 वर्दीधारी नक्सली ढेर, कई हथियार बरामद

बीजापुर, 26 फरवरी (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां इंद्रावती नदी क्षेत्र में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने दो नक्सलियों को ढेर किया है। वहीं घटनास्थल से हथियार, विस्फोटक और अन्य नक्सली सामग्री भी जब्त की गई है। इलाके में फिलहाल सर्च अभियान जारी है।

जानकारी के अनुसार, थाना जांगला क्षेत्र अंतर्गत इंद्रावती नदी इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिलने पर सुरक्षाबलों की संयुक्त टीम माओवादी विरोधी अभियान पर रवाना हुई थी। इसी दौरान आज सुबह सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। दोनों ओर से फायरिंग हुई, जिसके बाद माओवादी जंगल की ओर भाग निकले। मुठभेड़ के बाद चलाए गए सर्च अभियान में सुरक्षाबलों को दो वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। साथ ही घटनास्थल से एक एसएलआर राइफल, एक इंसास राइफल, एक 12 बोर राइफल, विस्फोटक सामग्री और अन्य नक्सली सामान भी जब्त किया गया है। इस मुठभेड़ की पुष्टि पुलिस अधीक्षक बीजापुर डॉ. जितेन्द्र यादव ने की है। वहीं बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पट्टलिंगम ने कहा कि क्षेत्र में सर्च अभियान जारी है और मुठभेड़ से जुड़ी विस्तृत जानकारी अलग से साझा की जाएगी।

भाजपा कार्यालय के लिए जमीन देने के विरोध मे लोहरसी के ग्रामीणों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव

धमतरी, 26 फरवरी (हाईवे चैनल)। धमतरी से लगे ग्राम लोहारसी में जिला भाजपा कार्यालय के लिए जमीन देने के विरोध में ग्रामीणों ने आज कलेक्ट्रेट का घेराव किया.

इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत के सरपंच ने पंचो के साथ मिलीभगत कर गोपनीय तौर पर जमीन को भाजपा के हवाले कर दिया है. जबकि उनके गांव में मवेशियों के चराने के लिए जगह नहीं है जिस जगह को आवंटित किया गया है उस जगह में गांव के छोटे बच्चे क्रिकेट और अन्य खेल खेलते हैं.

ब्रेकिंग न्यूज

सिर्फ माफी काफी नहीं, गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश हुई

नई दिल्ली, 26 फरवरी (न्यूज चैनल)। एनसीईआरटी की किताब पर उपजे विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कक्षा आठवीं की इस किताब के मामले में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी का माफी मांगना पर्याप्त नहीं है। न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया है। एनसीईआरटी की आठवीं कक्षा की किताब के विवादित अंश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई के दौरान एनसीईआरटी की आठवीं की उस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके अध्याय में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाला हिस्सा है। किताब में %न्यायपालिका में भ्रष्टाचार% वाले अंश को लेकर उपजे विवाद पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने सुनवाई की।

चूहा- सुनती हो, सुप्रीम कोर्ट 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' चैप्टर को लेकर नाराज हो गया है।

चुहिया- हां जी, फिर जस्टिस यशवंत वर्मा का कमरे भर पाए गए नोटों का रहस्य क्या है?

केंद्रीय कर्मचारियों पर 10 मार्च को होगा अंतिम फैसला! पगारसी की सैलरी में भी होगा भारी इजाफा

नई दिल्ली, 26 फरवरी (न्यूज चैनल)। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आने वाला समय आर्थिक खुशियों की सौगात ला सकता है। बीते बुधवार, 25 फरवरी 2025 को दिल्ली में नेशनल काउंसिल-जेसीएम की ड्राफ्टिंग कमेटी की एक मैराथन बैठक हुई, जिसने सरकारी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। लगभग दो घंटे तक चली इस उच्चस्तरीय चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु वह मेमोरेंडम तैयार करना था, जिसे जल्द ही सरकार और नए वेतन आयोग को सौंपा जाना है। कर्मचारियों की नजरें अब अगले पड़ाव पर टिकी हैं, क्योंकि इस बैठक में सैलरी स्ट्रक्चर को पूरी तरह बदलने का खाका तैयार किया गया है।

रेलवे कर्मचारियों की यूनियन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार, इस मंथन में भविष्य की सैलरी के ढांचे को लेकर पांच अहम मांगों पर सहमति बनाने की कोशिश की गई। सबसे प्रमुख मुद्दा फिटमेंट फैक्टर का रहा, जिसे कर्मचारी संघ 3.25 तक ले जाने की मांग पर अड़े हैं। यदि सरकार इस पर मुहर लगाती है, तो न्यूनतम वेतन में ऐतिहासिक उछाल देखने को मिलेगा। इसके साथ ही, बढ़ती महंगाई के दौर में न्यूनतम सैलरी की नई सीमा तय करने और सालाना इंक्रीमेंट को 3त्न से बढ़ाकर 7त्न करने के प्रस्ताव पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इतना ही नहीं, हाउस रेंट अलाउंस और मेडिकल अलाउंस जैसे भत्तों के पुनर्गठन और निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए एक बेहतर वेतन पैटर्न बनाने पर भी जोर दिया गया है। इस बैठक में केवल वेतन वृद्धि ही नहीं, बल्कि भेदभाव खत्म करने की आवाज भी बुलंद हुई। ऑल इंडिया एनपीएस इंप्लॉईज फेडरेशन के अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने मांग रखी कि केंद्र शासित प्रदेशों और स्वायत्त संस्थानों के लाखों कर्मचारियों को भी छ्ष्ठ्रू में उचित प्रतिनिधित्व मिले, ताकि केंद्र के नियम उन तक बिना किसी देरी के पहुंच सकें। वहीं, पुरानी पेंशन योजना की बहाली का मुद्दा अभी भी ब्रह्मास्त्र की तरह बना हुआ है। कर्मचारी संघों ने साफ कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ-साथ OPS की मांग उनकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रहेगी। हालांकि 25 फरवरी की चर्चा काफी सकारात्मक रही, लेकिन अभी तस्वीर पूरी तरह साफ होना बाकी है। जेसीएम की अगली बड़ी बैठक 10 मार्च को निर्धारित की गई है। इस बैठक में चर्चाओं को अंतिम रूप देकर एक संयुक्त मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा, जिसे औपचारिक रूप से आयोग को सौंप दिया जाएगा।

तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 2 पुलिसकर्मियों की मौत

तिल्दा-नेवरा/सिमगा, 26 फरवरी (हाईवे चैनल)। पौंसरी मार्ग पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में दो पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। हथबंद थाना क्षेत्र के उड़ेला-पौसरी मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को चपेट में ले लिया। इस दौरान एक आरक्षक की मौके पर मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल दूसरे आरक्षक की इलाज के दौरान रायपुर में मृत्यु हो गई।विवेचना के लिए निकले थे दोनों जवानजानकारी के अनुसार, आरक्षक क्रमांक 377 धर्मेंद्र यादव, जो जिला बलौदाबाजार के साइबर सेल में पदस्थ थे, तथा आरक्षक क्रमांक 809 प्रशांत धर दीवान, जो थाना हथबंद में तैनात थे, मंगलवार सुबह एक प्रकरण की विवेचना के सिलसिले में मोटरसाइकिल से निकले थे। सुबह लगभग 11 बजे वे हथबंद क्षेत्र के उड़ेला-पौसरी के पास पहुंचे ही थे कि सामने से आ रहे एक ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों जवान सड़क पर दूर जा गिरे।हादसे में आरक्षक धर्मेंद्र यादव की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। गंभीर रूप से घायल आरक्षक प्रशांत धर दीवान को तत्काल प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया, लेकिन उपचार के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया।पुलिस विभाग में शोकदो जवानों की असामयिक मृत्यु से पूरे जिले के पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है। सहकर्मियों के अनुसार दोनों जवान कर्तव्यनिष्ठ और जिम्मेदार अधिकारी थे।पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह अत्यंत पीड़ादायक और मार्मिक घटना है। विवेचना के दौरान निकले हमारी यूनिट के दो आरक्षकों की ट्रक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। विभाग मृत जवानों के परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है और हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दुर्घटना की जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं।गौरतलब है कि आरक्षक धर्मेंद्र यादव बेमेतरा जिले के ग्राम परसबोड़, थाना साजा के निवासी थे। वहीं आरक्षक प्रशांत धर दीवान बेमेतरा जिले के नवागढ़ क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। दोनों ही अपने परिवार के मुख्य सहारा थे। पुलिस ने ट्रक चालक और वाहन की जानकारी जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस दुखद घटना की खबर के बाद पूरे जिले में शोक का माहौल है और लोग दिवंगत जवानों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने दोनों मृत सिपाहियों को होनहार और समर्पित सिपाही बताया । सिमगा थाना में बहुत दिनों तक पदस्थ होने के कारण सिमगा वासियों में भी इन दोनों सिपाहियों की मृत्यु से गहहद्द शोक की लहर है । सिमगा ब्राम्हण समाज ने भी दोनों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

अधूरे रनवे से कैसे भरेगा बस्तर उड़ान! पर्यटन के क्षेत्र में असीम संभावनाओं के बाद भी फाइलों में कैद हवाई सेवा में विस्तार की योजना

जगदलपुर, 26 फरवरी (हाईवे चैनल)। बस्तर में हवाई सेवाओं के विस्तार की मांग वर्षों से उठ रही है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई आज भी सवालों के घेरे में है. जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट आज भी अधूरे रनवे और अधूरी प्रक्रियाओं का प्रतीक बना हुआ है. बस्तर जैसे आदिवासी और पर्यटन की अपार संभावनाओं वाले क्षेत्र के लिए हवाई सेवाएं विकास की रीढ़ मानी जाती हैं, लेकिन बस्तर में यह रीढ़ आज भी कमजोर है। जगदलपुर का मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जहाज भाटा के रूप में विकसित किया गया था, आज भी उसी दौर की बुनियादी संरचना से जूझ रहा है.

आज़ादी के बाद से अब तक एयरपोर्ट के रनवे की रिकार्पेटिंग का काम एक बार भी पूरी तरह नहीं हो पाया है. रनवे जर्जर होने की वजह से बड़े कमर्शियल विमानों की लैंडिंग संभव नहीं हो पा रही है. नतीजतन, जगदलपुर एयरपोर्ट केवल ज्ञ्रक जैसे छोटे रीजनल विमानों तक ही सीमित रह गया है. हवाई सेवाओं के विस्तार की हर घोषणा रनवे पर आकर थम जाती है। रनवे रिकार्पेटिंग के लिए कुल 25 करोड़ रुपए की आवश्यकता बताई गई है. राज्य सरकार की ओर से पहले 11 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी, लेकिन काम शुरू नहीं हो सका. अब एक बार फिर 14 करोड़ रुपए और जारी किए गए हैं, जिससे कुल राशि पूरी हो चुकी है. इसके बावजूद पीडब्ल्यूडी विभाग की टेंडर प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है. यानी पैसा होने के बावजूद काम कागज़ों में अटका हुआ है। इधर बस्तर में पर्यटन गतिविधियां बढ़ रही हैं, देश-विदेश से लोग बस्तर की संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य देखने आ रहे हैं..पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि सिर्फ रनवे ही नहीं, एयरपोर्ट की विजिबिलिटी भी एक बड़ी समस्या है. खराब मौसम या देर शाम होते ही फ्लाइट सेवाएं प्रभावित हो जाती हैं. यदि विजिबिलिटी सुधार और रनवे रिकार्पेटिंग का काम पूरा हो जाए, तो बस्तर में नियमित और भरोसेमंद हवाई सेवाएं संभव हो सकती हैं।